शनिवार, 27 जून, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

शेफाली के तूफान से भारत की दमदार जीत, सेमीफाइनल की उम्मीद बरकरार

age-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

रणवीर कपूर और यश ने दिखाई रामायण फिल्म की झलक

Page-05

प्रशांत किशोर की चुनावी वापसी

बांकीपुर उपचुनाव लड़ने का किया ऐलान

चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में बड़ा दांव खेलते हुए पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस घोषणा के साथ ही बिहार की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है और आगामी उपचुनाव को बेहद प्रतिष्ठित मुकाबला माना जा रहा है।प्रशांत किशोर ने कहा कि वह लंबे समय से बिहार में राजनीतिक बदलाव की बात कर रहे हैं और अब जनता के बीच सीधे जाकर जनादेश प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य की पारंपरिक राजनीति जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है, इसलिए वैकल्पिक राजनीति की आवश्यकता है।बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शहरी क्षेत्र होने के कारण यहां शिक्षित मतदाताओं की संख्या अधिक है और राजनीतिक दलों के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती है। ऐसे में प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं होगा, बल्कि इसे बिहार की भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाले मुकाबले के रूप में भी देखा जाएगा। प्रशांत किशोर पिछले कुछ वर्षों से जन सुराज अभियान के माध्यम से राज्यभर में सक्रिय रहे हैं और उन्होंने गांव-गांव जाकर जनसंवाद कार्यक्रम भी चलाया है।हालांकि उनके सामने चुनौती भी कम नहीं होगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA), राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और अन्य दल इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक सकते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि चुनाव में जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि निर्णायक भूमिका निभाएंगे।प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में उतरने से बिहार का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और अब सभी की निगाहें इस बहुप्रतीक्षित उपचुनाव पर टिक गई हैं।

राम मंदिर दान विवाद में बड़ा खुलासा

दो महीने में हुईं 70 चोरियां,8 आरोपी गिरफ्तार

अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान और चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो महीनों के दौरान मंदिर परिसर में चोरी की कुल 70 घटनाएं दर्ज की गईं। जांच के आधार पर अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।एसआईटी की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा दान पेटियों में डाले गए धन और चढ़ावे की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां थीं। कुछ घटनाओं में अंदरूनी लोगों की भूमिका की भी आशंका जताई गई है। जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि चोरी की घटनाएं सुनियोजित थीं या अलग-अलग समय पर हुईं।मामले के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है। विपक्षी दलों ने मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कई राजनीतिक दलों का कहना है कि देश की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक में इस तरह की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।जांच अधिकारियों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल रिकॉर्ड और कर्मचारियों से पूछताछ के आधार पर कई अहम सुराग मिले हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि चोरी की रकम कितनी थी और क्या इस मामले में कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था।मंदिर प्रशासन ने दावा किया है कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। परिसर में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई जा रही है तथा दान पेटियों की निगरानी के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी।इस बीच श्रद्धालुओं ने मांग की है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि करोड़ों लोगों की आस्था पर किसी तरह का आंच न आए।

राम मंदिर दान विवाद पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तीखा हमला, पारदर्शिता की मांग

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस मंदिर को करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक माना जाता है, वहां वित्तीय अनियमितताओं और चोरी की खबरें बेहद गंभीर हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार धार्मिक स्थलों के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन जब जवाबदेही और पारदर्शिता की बात आती है तो वह पीछे हट जाती है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर देश की आस्था का केंद्र है और यहां आने वाले श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ दान देते हैं। ऐसे में दान और चढ़ावे के प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।सपा प्रमुख ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को जनता के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि दान राशि के प्रबंधन की व्यवस्था क्या है और सुरक्षा में चूक कैसे हुई। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं ने सपा प्रमुख के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि सरकार मामले की जांच कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

नेविल डी'सूजा फुटबॉल ग्राउंड को लेकर आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर निशाना

उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने मुंबई के बांद्रा स्थित ऐतिहासिक नेविल डी'सूजा फुटबॉल ग्राउंड को लेकर महाराष्ट्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि सरकार इस प्रतिष्ठित खेल मैदान को हटाकर वहां एक कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रही है। आदित्य ठाकरे ने इसे मुंबई के खेल ढांचे पर बड़ा हमला बताते हुए कहा कि यदि ऐसा होता है, तो इससे हजारों खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को नुकसान पहुंचेगा।आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुंबई जैसे महानगर में पहले ही खेल मैदानों की भारी कमी है। लगातार बढ़ते शहरीकरण और निर्माण परियोजनाओं के कारण शहर में खुले मैदान तेजी से कम होते जा रहे हैं। ऐसे में नेविल डी'सूजा फुटबॉल ग्राउंड जैसे महत्वपूर्ण खेल स्थल को समाप्त करना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सार्वजनिक सुविधाओं और खेल अधोसंरचना की अनदेखी कर व्यावसायिक परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है।नेविल डी'सूजा फुटबॉल ग्राउंड मुंबई के फुटबॉल इतिहास का एक अहम हिस्सा रहा है। वर्षों से यह मैदान स्थानीय खिलाड़ियों, स्कूलों, क्लबों और विभिन्न फुटबॉल प्रतियोगिताओं का प्रमुख केंद्र रहा है। अनेक युवा खिलाड़ियों ने इसी मैदान से अपने खेल जीवन की शुरुआत की और आगे चलकर राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। खेल प्रेमियों का मानना है कि ऐसे मैदान केवल खेल गतिविधियों के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सामुदायिक जुड़ाव के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं।आदित्य ठाकरे ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाती है, तो शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) इसका कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने मांग की कि किसी भी विकास परियोजना को लागू करने से पहले स्थानीय नागरिकों, खिलाड़ियों, खेल संगठनों और विशेषज्ञों से व्यापक चर्चा की जानी चाहिए। उनका कहना है कि विकास आवश्यक है, लेकिन इसके लिए खेल सुविधाओं की बलि नहीं दी जानी चाहिए।

आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत का जलवा

24 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा देश

भारत ने ISSF Junior World Championship में शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। भारतीय निशानेबाजों ने प्रतियोगिता में कुल 24 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इनमें सात स्वर्ण, कई रजत और कांस्य पदक शामिल हैं।भारतीय दल के युवा खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दुनिया की कई मजबूत टीमों को पीछे छोड़ दिया। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारतीय निशानेबाजों ने निरंतर शानदार प्रदर्शन किया, जिससे देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली।विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि भारतीय शूटिंग के मजबूत भविष्य का संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में देश में शूटिंग के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं, आधुनिक उपकरण और वैज्ञानिक कोचिंग प्रणाली विकसित की गई है, जिसका सकारात्मक परिणाम अब अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में दिखाई दे रहा है।भारतीय खिलाड़ियों ने 10 मीटर एयर राइफल, एयर पिस्टल, मिश्रित टीम और अन्य स्पर्धाओं में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। कई युवा निशानेबाजों ने अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी दर्ज किए। कोचिंग स्टाफ ने खिलाड़ियों की सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, अनुशासन और लंबे समय से चल रही तैयारी को दिया।भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय राइफल संघ ने खिलाड़ियों की इस उपलब्धि की सराहना की है। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि जूनियर स्तर पर लगातार मिल रही सफलताएं भविष्य में ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजनों में भारत की संभावनाओं को मजबूत करेंगी।देशभर में खेल प्रेमियों और खेल प्रशासकों ने युवा निशानेबाजों की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। यह सफलता न केवल भारतीय शूटिंग के बढ़ते स्तर को दर्शाती है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी कि वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करें।

अमित शाह का 'ड्रग फ्री इंडिया 2029' विजन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को वर्ष 2029 तक नशामुक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर एक नया विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस दस्तावेज़ में अगले तीन वर्षों यानी 2026 से 2029 के बीच की अवधि को सबसे अहम बताया गया है। गृह मंत्रालय का मानना है कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें समन्वय के साथ काम करें, तो भारत को नशीले पदार्थों के कारोबार से काफी हद तक मुक्त किया जा सकता है।विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार, नशे के खिलाफ लड़ाई को केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे सामाजिक आंदोलन का रूप दिया जाएगा। स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों और धार्मिक संस्थाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य न केवल नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना है, बल्कि नशे की लत से पीड़ित लोगों के पुनर्वास और उपचार पर भी विशेष ध्यान देना है।गृह मंत्री ने कहा कि देश में नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, राज्य पुलिस और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया गया है। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाएगी और ड्रोन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं पर निगरानी मजबूत करने की योजना है।

वेनेजुएला के लिए भारत बना संकटमोचक

'ऑपरेशन अमिस्ताद' के तहत भेजी राहत और मेडिकल टीम

वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप में 245 लोगों की मौत और 4300 से अधिक लोग घायल हुए हैं।भारत ने 'ऑपरेशन अमिस्ताद' शुरू कर राहत सामग्री, मेडिकल टीम और मोबाइल अस्पताल भेजे हैं।तुर्की समेत कई देशों ने भी बचाव और राहत कार्यों के लिए सहायता का ऐलान किया है।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

भारत ने एक बार फिर वैश्विक मानवीय सहायता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित करते हुए भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में अब तक 245 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,300 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हजारों मकान धराशायी हो गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं और राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं।इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने तत्काल राहत अभियान शुरू किया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जानकारी दी कि भारत ने 'ऑपरेशन अमिस्ताद' की शुरुआत कर दी है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के दो सी-17 ग्लोबमास्टर विमान राहत सामग्री और मेडिकल सहायता लेकर वेनेजुएला के लिए रवाना हो चुके हैं।इन विमानों में भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सकों और नर्सों की विशेष टीम के साथ 35 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। राहत सामग्री में दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, आपातकालीन उपयोग की सामग्री, खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा, दो अत्याधुनिक 'भीष्म क्यूब्स' भी भेजे गए हैं। ये विशेष मोबाइल अस्पताल हैं, जो युद्ध या प्राकृतिक आपदा के दौरान तत्काल चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं।भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट स्थानीय प्रशासन और अस्पतालों के साथ मिलकर घायलों का इलाज करेगी। यह यूनिट सर्जरी, आपातकालीन उपचार और गंभीर रूप से घायल मरीजों की देखभाल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात में यह सहायता बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि भूकंप के बाद वेनेजुएला की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी दबाव है।विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां की जनता के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता और आपदा राहत भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा है।गौरतलब है कि भारत इससे पहले भी तुर्की-सीरिया भूकंप समेत कई अंतरराष्ट्रीय आपदाओं में तेजी से राहत पहुंचा चुका है। इसी कड़ी में तुर्की ने भी वेनेजुएला की सहायता के लिए बचाव दल और मानवीय सहायता कर्मियों को भेजने की घोषणा की है। तुर्की की आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (AFAD) ने बताया कि 38 सदस्यीय विशेष टीम, खोजी कुत्तों, चिकित्सा दल और बचाव वाहनों के साथ एक ए-400एम सैन्य विमान वेनेजुएला भेजा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के इन प्रयासों से राहत एवं बचाव कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

रूस को चुनौती देने के लिए नाटो की नई रणनीति

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

बर्फीले आर्कटिक क्षेत्र को लेकर दुनिया की महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। रूस की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच नाटो देशों ने आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों का मानना है कि आने वाले वर्षों में आर्कटिक वैश्विक राजनीति का सबसे अहम सामरिक क्षेत्र बन सकता है।रिपोर्टों के अनुसार, रूस ने आर्कटिक क्षेत्र में अपने सैन्य ठिकानों और परमाणु क्षमताओं को लगातार मजबूत किया है। रूस के पास इस क्षेत्र में 40 से अधिक आइसब्रेकर जहाज हैं, जबकि नाटो देशों की क्षमता अपेक्षाकृत कम मानी जाती है। यही वजह है कि नाटो अब इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।हाल ही में नॉर्वे में 30 हजार से अधिक सैनिकों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में संभावित रूसी चुनौती का मुकाबला करने की तैयारी करना था। नाटो महासचिव मार्क रुटे ने भी सदस्य देशों से इस क्षेत्र में निवेश और सैन्य सहयोग बढ़ाने की अपील की है।विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र में नए समुद्री मार्ग खुल रहे हैं और खनिज संसाधनों तक पहुंच आसान हो रही है। इसी वजह से अमेरिका, रूस और अन्य शक्तियां इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। आने वाले समय में आर्कटिक वैश्विक शक्ति संतुलन का नया केंद्र बन सकता है।

जहरीली गैस की वजह मौत होने की आशंका

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पश्चिमी दिल्ली के मुंडका औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक में उतरे तीन मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई है। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, फैक्ट्री नंबर 93/8, मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया से सूचना मिलने पर दो फायर टेंडर मौके पर भेजे गए और मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, एक व्यक्ति पहले सेप्टिक टैंक में उतरा और जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गया। फिर, उसे बचाने के लिए 2 अन्य व्यक्ति भी एक-एक कर टैंक में उतरे, लेकिन वे भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। बाद में दमकलकर्मियों ने तीनों को सेप्टिक टैंक से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 38 साल के अरुण पुत्र अजीत सिंह, 32 वर्ष के संदीप पुत्र पालेराम और 42 साल के चांद पुत्र राजू के रूप में हुई है। ये तीनों सुल्तानपुरी के इंद्रा झील इलाके के रहने वाले थे। इस मामले की जांच मुंडका थाना पुलिस ने शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एसआई प्रवेश ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर जहरीली गैस के कारण दम घुटने से मौत होने की आशंका है। हादसे की खबर मिलते ही लोकल स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मौके का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई शुरू की। अब यह भी मालूम किया जा रहा है कि क्या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था। मजदूरों को सेफ्टी इक्विपमेंट उपलब्ध कराए गए थे या नहीं। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि सेप्टिक टैंक के अंदर जहरीली गैस का लेवल काफी ज्यादा रहा होगा। ऐसे मामलों में बिना पर्याप्त ऑक्सीजन के इंतजाम के सेप्टिक टैंक में उतरना बेहद खतरनाक होता है। इसी कारण से अक्सर सेप्टिक टैंक के अंदर जाते ही जहरीली गैस से मजदूरों की मौत हो जाती है।

नाटो में बढ़ी दरार! ट्रंप के दबाव के बीच रक्षा खर्च बढ़ाने पर मचा घमासान

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच बढ़ते मतभेदों ने एक बार फिर नाटो (NATO) की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगले महीने तुर्किये की राजधानी अंकारा में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन से पहले संगठन के भीतर रक्षा खर्च को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। नाटो के उप सर्वोच्च कमांडर एयर चीफ मार्शल सर जॉन स्ट्रिंगर ने सदस्य देशों से रक्षा बजट में भारी वृद्धि करने की अपील की है।दरअसल, राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से यूरोपीय देशों पर अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर अत्यधिक निर्भर रहने का आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में ईरान संघर्ष के दौरान कुछ यूरोपीय देशों द्वारा अमेरिका का खुलकर समर्थन नहीं करने से ट्रंप की नाराजगी और बढ़ गई है। ट्रंप ने साफ कहा है कि नाटो देशों को अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा रक्षा पर खर्च करना चाहिए।नाटो महासचिव मार्क रुटे ने हाल ही में व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात कर संगठन में एकजुटता बनाए रखने की कोशिश की। रुटे ने दावा किया कि यूरोपीय देश रक्षा खर्च में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ सदस्य देश अभी भी पीछे हैं।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका यूरोप में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करता है, तो यूरोपीय देशों पर अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि नाटो सदस्य देशों में सैन्य उत्पादन, हथियार निर्माण और सैनिक तैनाती को लेकर नई रणनीति तैयार की जा रही है।राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अंकारा शिखर सम्मेलन नाटो के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि सदस्य देश रक्षा खर्च और सामूहिक सुरक्षा पर सहमति नहीं बना पाए, तो संगठन के भीतर मतभेद और गहरे हो सकते हैं।

रूस की नई साजिश का अलर्ट! बाल्टिक देशों और पोलैंड पर 'उकसावे वाली कार्रवाई' की आशंका

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप में एक नए भू-राजनीतिक संकट की आशंका गहराने लगी है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों और नाटो से जुड़े अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रूस आने वाले महीनों में बाल्टिक देशों—एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया—या फिर पोलैंड के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाई कर सकता है। इस चेतावनी के बाद पूरे यूरोप में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, रूस प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष की बजाय सीमित ड्रोन हमले, साइबर अटैक, सीमा उल्लंघन, जीपीएस सिग्नल जाम करने या अन्य हाइब्रिड ऑपरेशन के जरिए नाटो की एकजुटता और प्रतिक्रिया क्षमता की परीक्षा ले सकता है। पश्चिमी देशों को आशंका है कि रूस यह जानने की कोशिश कर सकता है कि किसी छोटे सदस्य देश पर दबाव पड़ने की स्थिति में नाटो कितनी मजबूती से जवाब देता है।लातविया की खुफिया एजेंसी ने हाल ही में जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि रूस की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस ने अपनी सैन्य और साइबर क्षमताओं को बरकरार रखा है। इसके मद्देनजर पोलैंड, लिथुआनिया और अन्य बाल्टिक देशों ने अपनी सीमाओं पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है तथा निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।नाटो अधिकारियों का मानना है कि यूक्रेन में लंबे समय से जारी युद्ध के बीच रूस पश्चिमी देशों पर रणनीतिक दबाव बनाने के लिए नए मोर्चे खोलने की कोशिश कर सकता है। हालांकि फिलहाल किसी बड़े सैन्य हमले की आशंका कम बताई जा रही है, लेकिन यूरोपीय देशों ने किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं।विशेषज्ञों का कहना है कि यदि रूस और नाटो के बीच तनाव और बढ़ता है, तो इसका असर केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। ऐसे में दुनिया की नजरें अब रूस की अगली रणनीति और नाटो की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं।

संपादक की कलम से

केंद्र सरकार में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों ने एक बार फिर राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकातों के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि सरकार जल्द ही अपनी टीम में बदलाव कर सकती है। यद्यपि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन भारतीय राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश भी होता है।लोकतांत्रिक व्यवस्था में मंत्रिमंडल किसी भी सरकार का चेहरा होता है। मंत्रियों के कार्य, उनकी कार्यशैली और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता सीधे सरकार की छवि को प्रभावित करती है। ऐसे में समय-समय पर मंत्रिमंडल में बदलाव करना एक स्वाभाविक और आवश्यक प्रक्रिया है। इससे न केवल सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने का अवसर मिलता है, बल्कि नई ऊर्जा और नए विचारों को भी स्थान मिलता है।वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो आगामी महीनों और वर्षों में बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि सत्तारूढ़ दल सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपने राजनीतिक समीकरणों को मजबूत करने का प्रयास करे। सहयोगी दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना भी गठबंधन राजनीति की मजबूरी और आवश्यकता दोनों है।हालांकि, केवल राजनीतिक संतुलन साधना ही पर्याप्त नहीं है। मंत्रिमंडल में शामिल व्यक्तियों का चयन उनकी कार्यक्षमता, प्रशासनिक दक्षता और जनविश्वास के आधार पर होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता यह अपेक्षा करती है कि सरकार में वही लोग जिम्मेदारी संभालें जो अपने विभागों में प्रभावी प्रदर्शन कर सकें और जनसमस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील हों।आज देश के सामने रोजगार, शिक्षा, महंगाई, कृषि और स्वास्थ्य जैसी अनेक चुनौतियां हैं। ऐसे समय में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन यदि इन मुद्दों के समाधान को केंद्र में रखकर किया जाता है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकता है। लेकिन यदि फेरबदल केवल राजनीतिक संदेश देने तक सीमित रह जाता है, तो उसका अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाएगा।अंततः किसी भी सरकार की सफलता उसके मंत्रियों की संख्या या चेहरे बदलने से नहीं, बल्कि नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से तय होती है। जनता को बदलाव से अधिक परिणाम चाहिए। इसलिए संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल का वास्तविक मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह देश की शासन व्यवस्था को कितना अधिक उत्तरदायी, प्रभावी और जनोन्मुख बनाता है।

भाजपा का यूपी में बड़ा संगठनात्मक दांव

नीरज सिंह और पूजा पाल को मिली अहम जिम्मेदारी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा जारी नई सूची में कुल 46 पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सबसे अधिक चर्चा पूर्व रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह के पुत्र नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने की हो रही है।भाजपा ने इस फेरबदल में सबसे बड़ा बदलाव क्षेत्रीय अध्यक्षों के स्तर पर किया है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए नई टीम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने के उद्देश्य से प्रदेश स्तर पर व्यापक फेरबदल किया है। राजनीतिक जानकार इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की सबसे बड़ी संगठनात्मक कवायद मान रहे हैं।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा जारी नई सूची में कुल 46 पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सबसे अधिक चर्चा पूर्व रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह के पुत्र नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने की हो रही है। नीरज सिंह लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे हैं, लेकिन पहली बार उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे पार्टी के भीतर नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।इसके अलावा पूर्व सांसद प्रियंका रावत, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, सुरेश मौर्य और राजेश यादव को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, प्रदेश महामंत्री पद पर राम प्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है।भाजपा ने इस फेरबदल में सबसे बड़ा बदलाव क्षेत्रीय अध्यक्षों के स्तर पर किया है। पार्टी ने अपने सभी छह क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदल दिया है। पूर्वांचल, अवध, ब्रज, पश्चिम, काशी और गोरखपुर क्षेत्रों में नए चेहरों को मौका दिया गया है। गोरखपुर क्षेत्र की कमान विनोद राय को सौंपी गई है। पार्टी का मानना है कि नए नेतृत्व के जरिए बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत किया जा सकेगा।राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा ने यह फेरबदल बेहद सोच-समझकर किया है। लोकसभा चुनाव में पार्टी को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। खासकर पिछड़ा वर्ग और दलित मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ को लेकर सवाल उठे थे। ऐसे में भाजपा ने संगठन में ओबीसी, दलित, महिला और युवा नेताओं को अधिक प्रतिनिधित्व देकर स्पष्ट संकेत दिया है कि वह 2027 के चुनाव को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती।विपक्ष ने हालांकि इस बदलाव पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाजपा संगठन बदलकर जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भी इसे "चुनावी घबराहट" का परिणाम बताया है।हालांकि भाजपा नेताओं का दावा है कि नई टीम पार्टी को पहले से अधिक मजबूत बनाएगी और बूथ स्तर तक संगठन का विस्तार करेगी। राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा भी तेज हो गई है कि संगठन में बदलाव के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और अधिक गर्माने के आसार हैं।

अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात, सियासी हलचल तेज

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

केंद्र सरकार में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं के बीच गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार और गर्म कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात के दो दिन बाद अमित शाह का राष्ट्रपति भवन पहुंचना राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से इस मुलाकात को नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है, लेकिन दिल्ली के सत्ता गलियारों में इसे संभावित कैबिनेट विस्तार और फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है।सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी आगामी संसद के मानसून सत्र से पहले अपनी मंत्रिपरिषद में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस फेरबदल में कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, जबकि कुछ नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। खासकर सहयोगी दलों को अधिक प्रतिनिधित्व देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।राजनीतिक हलकों में जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनमें श्रीकांत शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और नीतीश कुमार प्रमुख हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम और शिवसेना (उद्धव गुट) के छह सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र से एनडीए सहयोगियों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। हाल के महीनों में प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष के हमलों के बाद उनके मंत्रालय में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के विभाग को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। हालांकि भाजपा नेतृत्व ने अभी तक इन अटकलों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फेरबदल केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक भी होगा। अगले डेढ़ वर्ष में बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ-साथ सहयोगी दलों को भी मजबूत संदेश देना चाहती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की अटकलें तेज धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी के विभागों में बदलाव की चर्चा

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

केंद्र सरकार में बड़े मंत्रिमंडलीय फेरबदल की अटकलों ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि अगले कुछ दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार, सरकार सहयोगी दलों को अधिक प्रतिनिधित्व देने और कुछ मंत्रालयों में प्रदर्शन के आधार पर बदलाव करने पर विचार कर रही है।राजनीतिक सूत्रों की मानें तो इस संभावित फेरबदल में सबसे अधिक चर्चा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर हो रही है। हाल के महीनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों और विपक्ष के लगातार हमलों के बीच उनके मंत्रालय की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। ऐसे में उनके विभाग में बदलाव या नई जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना जताई जा रही है।इसी तरह केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के विभाग में भी बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी पंजाब से किसी नए सिख चेहरे को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है।सूत्रों के अनुसार, भाजपा अपने सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में अधिक प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर रही है। इस कड़ी में जेडीयू नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे तथा कुछ अन्य सहयोगी दलों के नेताओं के नाम चर्चा में हैं। महाराष्ट्र और बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए यह फेरबदल राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।बताया जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के विभागों को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है, हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो इसका सीधा असर कई राज्यों की राजनीति पर पड़ सकता है। खासकर बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भाजपा आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए नए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर सकती है। अब सबकी नजरें प्रधानमंत्री कार्यालय और भाजपा नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।

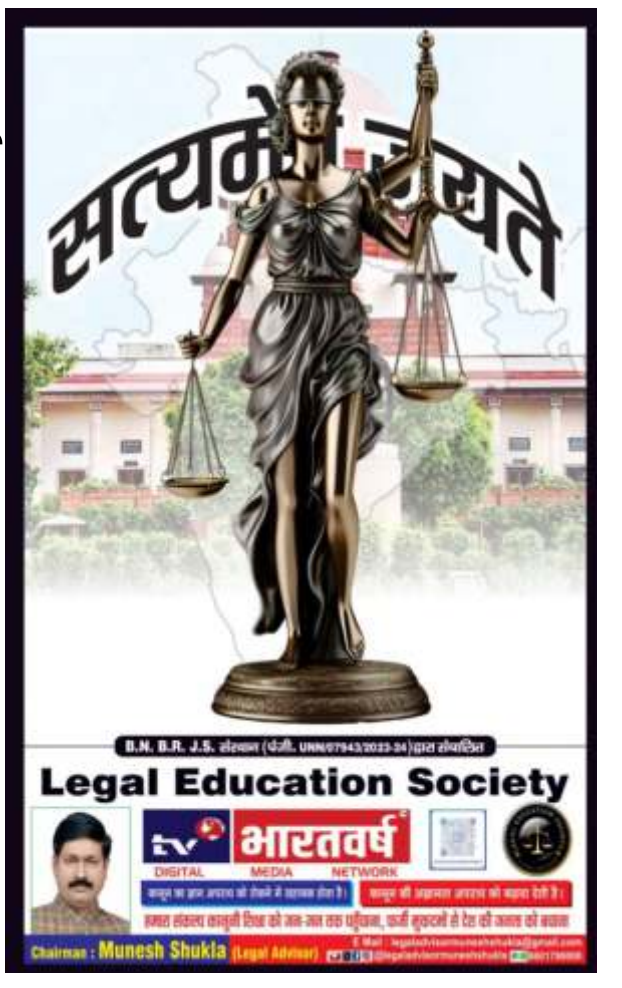

पूजा खेड़कर प्रकरण के बाद UPSC सख्त AI की मदद से 569 संदिग्ध आवेदन किए खारिज

आप सभी को पूजा खेड़कर का नाम तो याद ही होगा. आपको याद होगा कि किस तरह एक ट्रेनी IAS अफसर पर अपनी पहचान और दस्तावेजों में कथित बदलाव कर UPSC के नियमों को दरकिनार करने के आरोप लगे थे. देशभर में इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं और UPSC की चयन प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े हो गए थे. अब आगे इस तरह की किसी भी स्थिति से बचने के लिए UPSC ने कदम उठाया है. इसके लिए आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा लिया है. दरअसल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 में पहली बार AI का इस्तेमाल किया और बड़ी कार्रवाई की. एग्जाम से पहले ही UPSC ने 569 ऐसे आवेदनों को खारिज कर दिया, जो नियमों के अनुसार अयोग्य पाए गए. इनमें कई ऐसे उम्मीदवार शामिल थे जिन्होंने तय सीमा से अधिक प्रयास कर लिए थे या एज लिमिट क्रॉस कर चुके थे. वहीं, कुछ मामलों में एक ही व्यक्ति द्वारा कई आवेदन भी किए गए थे. रिपोर्ट्स के अनुसार ये कदम 2024 के चर्चित पूजा खेडकर मामले के करीब दो साल बाद उठाया गया है. पूजा खेडकर पर आरोप था कि उन्होंने नाम और माता-पिता के नाम में बदलाव कर निर्धारित प्रयासों की सीमा पूरी होने के बावजूद UPSC परीक्षा दी थी. बाद में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी और सेवा से भी बर्खास्त कर दिया गया था. अब तक UPSC इस तरह की जांच इंटरव्यू चरण में करता था, यानी तब जब उम्मीदवार

प्रीलिम्स और मेन्स दोनों परीक्षाएं पास कर लेते थे. लेकिन इस बार आयोग ने तकनीक का सहारा लेते हुए आवेदन चरण में ही जांच शुरू कर दी. UPSC के अनुसार इस साल सिविल सेवा परीक्षा के लिए 8.18 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जबकि करीब 5.49 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. पिछले साल की तुलना में आवेदनों की संख्या में कमी भी दर्ज की गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 94 प्रतिशत उम्मीदवारों ने आधार आधारित सत्यापन का विकल्प चुना था. बाकी करीब 49 हजार आवेदनों की जांच AI की मदद से की गई. AI ने उम्मीदवारों के नाम, माता-पिता के नाम, जन्मतिथि और फोटो का मिलान कर डुप्लीकेट आवेदनों की पहचान की. इसके बाद आयोग ने पिछले 15 वर्षों के रिकॉर्ड के आधार पर यह भी जांचा कि कहीं उम्मीदवार अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम प्रयासों या आयु सीमा को तो पार नहीं कर चुके हैं. AI से चेकिंग के समय 43,497 ऐसे उम्मीदवार भी मिले जिन्होंने अपने पिछले प्रयासों की तुलना में इस बार श्रेणी बदली थी. उदाहरण के लिए, कुछ उम्मीदवारों ने पहले सामान्य वर्ग (General) में आवेदन किया था और इस बार EWS या अन्य आरक्षित श्रेणियों में आवेदन किया. UPSC ने ऐसे सभी उम्मीदवारों को ईमेल भेजकर जानकारी सत्यापित की. जांच के बाद 133 आवेदन केवल इसी कारण रद्द कर दिए गए क्योंकि उम्मीदवार अपनी नई श्रेणी के हिसाब से अनुमत प्रयासों की सीमा पार कर चुके थे.

एससी और ओबीसी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ए अहम फैसला

अगर आप सरकारी स्कॉलरशिप का फायदा लेते हैं.तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की हो सकती है. केंद्र सरकार ने एससी और ओबीसी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक अहम फैसला लिया है.सरकार के इस फैसले से अब कई मामलों में छात्रों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी. इससे आवेदन करने में समय की बचत होगी और छात्र आसानी से स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं. अब तक छात्रों को कई स्कॉलरशिप योजनाओं में आवेदन करने के लिए निवास पर प्रमाण पत्र देना जरूरी माना जाता था. निवास प्रमाण पत्र में छात्र की स्थायी निवास की पूरी जानकारी होती है,कि छात्र किस राज्य का और किस इलाके का स्थाई निवासी है लेकिन इस डॉक्यूमेंट को बनवाने में कई बार छात्रों को और उनके परिवारों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था. कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते इतनी देर हो जाती थी कि आवेदक का समय ही निकल जाता था. जिसकी वजह से सरकार ने अब नियमों में बदलाव का कदम उठाया है देश में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र जो पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर रहते हैं ऐसे छात्र को स्कॉलरशिप के लिए निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वापस घर जाना पड़ता था जिसमें उनका काफी समय और पैसा बर्बाद होता था. अब आवेदन प्रक्रिया आसान होने से ऐसे छात्रों को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है. कई बार सिर्फ छात्र ही नहीं उनके माता-पिता को भी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी. कई बार अभिभावकों को निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और कुछ मामलों में काम को जल्दी करने के लिए अधिक खर्च भी करना पड़ता था. पर अब इस नए बदलाव से इस तरह की होने वाली परेशानियों से बचने की काफी संभावना बढ़ गई है.

सेरेना-वीनस की जोड़ी फिर कोर्ट पर, विंबलडन में दिखेगा पुराना जलवा

फीफा वर्ल्ड कप 2026: जर्मनी बाहर, इक्वाडोर ने इतिहास रच दिया

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार (लोकल समय) को ग्रुप-स्टेज के अहम मुकाबले हुए, जिसमें तीन और ग्रुप के मैच खत्म हुए और कई टीमों ने कड़े मुकाबलों के बीच राउंड ऑफ़ 32 में अपनी जगह पक्की की। इक्वाडोर ने दिन का एक ऐतिहासिक नतीजा देते हुए, यूरोप की दिग्गज टीम और चार बार की चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया। ESPN के मुताबिक, आइवरी कोस्ट ने भी कुराकाओ पर 2-0 की शानदार जीत के साथ राउंड ऑफ़ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। नीदरलैंड्स ने ट्यूनीशिया को 3-1 से हराकर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और अपने ग्रुप में टॉप पर रहे, जबकि जापान और स्वीडन के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहने के बाद दोनों टीमें नॉकआउट राउंड में पहुँच गईं। ग्रुप D के एक और मैच में, तुर्की ने मेज़बान अमेरिका को 3-2 से हराया; इस मैच का क्वालिफिकेशन के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा। वहीं, पैराग्वे के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल किया; पैराग्वे अभी भी दूसरे मैचों के नतीजों के आधार पर नॉकआउट में जगह बनाने की दौड़ में बना हुआ है। जर्मनी पर 2-1 की जीत के साथ इक्वाडोर दूसरी बार FIFA वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ा है; इससे पहले उसने 2006 में यह उपलब्धि हासिल की थी, लेकिन तब वह राउंड ऑफ़ 16 में इंग्लैंड से हारकर बाहर हो गया था। ESPN के अनुसार, यह दूसरा मौका था जब इक्वाडोर ने पिछड़ने के बाद वर्ल्ड कप मैच जीता; इससे पहले 2014 में होंडुरास के खिलाफ़ ऐसा हुआ था। जर्मनी ने दूसरे मिनट में लेरॉय साने के गोल से बढ़त बनाई। यह गोल 1 मिनट 49 सेकंड पर हुआ, जो FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास में जर्मनी का दूसरा सबसे तेज़ गोल था। इससे पहले 1934 के टूर्नामेंट में अर्नेस्ट लेहनर ने पहले मिनट में गोल किया था।

शेफाली के तूफान से भारत की दमदार जीत, सेमीफाइनल की उम्मीद बरकरार

मैनचेस्टर में ICC महिला T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मैच में बांग्लादेश को पांच विकेट से हराकर, शैफाली वर्मा की हाफ-सेचुरी और राधा यादव व श्री चार की शानदार गेंदबाजी की मदद से भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखीं। इस जीत के साथ, भारत ग्रुप A में तीन जीत और एक हार के साथ छह अंक लेकर दूसरे स्थान पर है; ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है जिसने अपने सभी चार मैच जीते हैं। भारत को अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच और खेलना है और वह अभी आधिकारिक तौर पर सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा है; दक्षिण अफ्रीका, जिसने अपने तीन में से दो मैच जीते हैं, भी सेमीफाइनल में पहुंचने की मजबूत दावेदार है। मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला किया और 20 ओवर में 136/8 रन बनाए। जुएरिया फ़िरदौस (31 गेंदों में 33 रन, पांच चौकों के साथ) और शोभना मोस्तरी (26 गेंदों में 22 रन, दो चौकों के साथ) ने दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की और कप्तान निगार सुल्ताना (27 गेंदों में 32 रन, चार बाउंड्री के साथ) ने बांग्लादेश को एक ठीक-ठाक स्कोर तक पहुँचाने में मदद की। भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों में राधा यादव (3/28) और श्री चरणी (2/21) शामिल थीं, जबकि रेणुका ठाकुर और नंदिनी शर्मा को भी एक-एक विकेट मिला। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने स्मृति मंधाना (8) का विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन शेफाली (34 गेंदों में 53 रन, जिसमें आठ चौके और एक छक्का शामिल था) और यास्तिका भाटिया (18 गेंदों में 23 रन, जिसमें तीन चौके शामिल थे) ने दूसरे विकेट के लिए 45 रन जोड़े। भारत का स्कोर 76/2 से 98/4 हो गया और टीम थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स (15 गेंदों में 26 रन, जिसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल था), कप्तान हरमनप्रीत कौर (13*) और दीप्ति शर्मा (5*) ने भारत को 19 गेंदें बाकी रहते पांच विकेट से जीत दिलाई। मैच के दौरान, भारतीय स्पिनर चारानी ने इतिहास रच दिया; उन्होंने एक ही ICC महिला T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में पूनम यादव को पीछे छोड़ दिया।

बेल्जियम पर जीत से न्यूजीलैंड के लिए खुलेगा नॉकआउट का दरवाजा

विश्व कप में कई ऐसी टीमें हैं जिनकी रैंकिंग न्यूजीलैंड से बेहतर है लेकिन वे अपने आखिरी ग्रुप चरण मैच में नॉकआउट चरण में जगह बनाने की बिना किसी उम्मीद के साथ उतरेगी। न्यूजीलैंड के कोच डैरेन बैजली ने बेल्जियम के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले मैच से पहले कहा, "हमारी स्थिति (नॉकआउट चरण में जगह नहीं बना पाने की उम्मीद) ऐसी नहीं है। अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि अगर हम जीतते हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे।" यह स्थिति तब असंभव लग रही थी जब मौजूदा विश्व कप की सबसे कम रैंकिंग वाली टीमों में से एक न्यूजीलैंड को बेल्जियम, मिस्र और ईरान के साथ ग्रुप जी में रखा गया था लेकिन 48 टीम वाले नए प्रारूप और ग्रुप में अप्रत्याशित नतीजों की वजह से टीम पहली बार ग्रुप चरण से आगे बढ़ने से बस एक जीत दूर है। बैजली ने कहा, "चीजें वैसी नहीं होतीं जैसी आप उम्मीद करते हैं। फुटबॉल में तो बिल्कुल नहीं।" बेल्जियम के खिलाफ जीत न्यूजीलैंड को ग्रुप जी में दूसरे स्थान और नॉकआउट में पहुंचा सकती है लेकिन इसके लिए मिस्र और ईरान के बीच शुक्रवार को ही होने वाला मैच ड्रॉ रहना चाहिए। बेल्जियम के खिलाफ जीत नहीं मिलने पर न्यूजीलैंड के लिए ग्रुप चरण से आगे बढ़ने का मौका खत्म हो जाएगा। फीफा रैंकिंग में 84वें स्थान पर काबिज न्यूजीलैंड के कोच बैजली ने कहा, "अब हमारे लिए स्थिति बिल्कुल साफ है जो कि अच्छी बात है।

93 की उम्र में भी थिएटर में काम कर रही महिला

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक 93 साल की महिला मूवी थियेटर में काम कर अपना गुजारा कर रही हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही फिल्म खत्म होती है, दर्शक हॉल से बाहर निकलते दिखते हैं. उसी वक्त महिला अपना काम शुरू कर देती हैं. वह वहां बिखरे कचरे को धीरे-धीरे समेटती है. वह खाली बोतलें और खाने के पैकेट इकट्ठा करती हैं, ताकि अगला शो समय पर शुरू हो सके. ⊙

मिलावट का नया तरीका या कलाकार की जादुई कला?

समोसे पर ब्रश से रंग का अनोखा खेल

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में एक शख्स समोसे जैसी दिखने वाली चीजों पर ब्रश से रंग लगाता नजर आता है. इसके बाद कुछ लोगों ने मिलावट का दावा किया.

एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को कन्फ्यूज कर दिया है.

पहली नजर में ऐसा लगता है कि एक शख्स समोसों पर ब्रश से रंग लगा रहा है. वीडियो सामने आते ही कई लोगों ने इसे खाने में मिलावट का मामला बता दिया, जबकि एक दावा ये भी है कि ये खाने वाले समोसे नहीं, बल्कि सजावट के लिए बनाए गए नकली समोसे हैं. फिलहाल वीडियो को लेकर जमकर बहस छिड़ी हुई है.

वायरल क्लिप में एक व्यक्ति जमीन पर बैठा दिखाई देता है. उसके आसपास समोसे जैसी चीजें रखी हैं. कुछ का रंग हल्का है, जबकि कुछ पहले से सुनहरे रंग की दिखाई देती हैं. वह ब्रश की मदद से इन पर रंग लगाता नजर आता है. पास में रंग से भरे छोटे-छोटे डिब्बे भी रखे हुए हैं. ये नजारा लोगों को उलझन में डाल रहा है, क्योंकि यह किसी कुकिंग प्रोसेस से ज्यादा पेंटिंग जैसा दिखाई देता है.यह वीडियो X पर शेयर किये गया है. जिसका कैप्शन है- मुझे लगा था समोसे शुद्ध होते हैं, लेकिन यहां भी मिलावट हो रही है. इसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया और कई लोगों ने खाने की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए. वीडियो पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. एक यूजर ने लिखा कि समोसे को रंगने की क्या जरूरत है. ⊙

सच्चाई अब भी साफ नहीं

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो में दिख रही वस्तुएं वास्तव में खाने वाले समोसे हैं या सजावट के लिए तैयार किए गए खिलौने . इस वीडियो या उससे जुड़े दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.फिलहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अपनी-अपनी समझ के अनुसार इसकी अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं. ⊙

कभी सीट पर बैठा तो कभी महिला की गोद में

दिल्ली मेट्रो में बंदर की 'मस्ती'

दिल्ली मेट्रो से जुड़े वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कभी सीट को लेकर झगड़ा, कभी रील बनाने के लिए डांस और कभी अजीबोगरीब हरकतें. लेकिन इस बार मामला यात्रियों का नहीं, बल्कि एक बंदर का है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक बंदर दिल्ली मेट्रो के डिब्बे के अंदर आराम से घूमता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं- आखिर दिल्ली मेट्रो में बंदर घुसा कैसे? बताया जा रहा है कि यह वीडियो दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन का है. वायरल क्लिप में बंदर कभी यात्रियों की सीटों के पास घूमता है तो कभी एक महिला की गोद में जाकर बैठ जाता है. इतना ही नहीं, वीडियो में वह महिला के चेहरे के बेहद करीब आता है, जिसे सोशल

मीडिया पर कई लोग 'किस' करने जैसा बता रहे हैं. हालांकि महिला पूरे समय शांत नजर आती है और उसे किसी तरह की घबराहट नहीं दिखती वीडियो शेयर करने वाले कई यूजर्स का दावा है कि यह घटना सराय काले खां मेट्रो स्टेशन के पास हुई. वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने दिल्ली मेट्रो के आधिकारिक X हैंडल को टैग करते हुए पूछा कि इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बंदर मेट्रो के अंदर कैसे पहुंच गया. ⊙

37 लाख रुपये खर्च कर फंसे दूल्हे ने कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

3 दिन में शादी, 9वें दिन टूटा रिश्ता

शादी से पहले दोनों ने सिर्फ 5 मिनट बात की थी. तीन दिन बाद शादी हो गई. लेकिन शादी के महज 9 दिन बाद पति को ऐसा सच पता चला कि उसने तलाक लेने का फैसला कर लिया. अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और लाखों रुपये का विवाद अलग खड़ा हो गया है.

यह मामला चीन के झेजियांग प्रांत का है, जहां 32 वर्षीय गु (बदला हुआ नाम) अपने माता-पिता की इकलौती संतान है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, 32 वर्षीय गु की लंबे समय से शादी नहीं हो पा रही थी. परिवार भी इसे लेकर परेशान था. आखिरकार उन्होंने एक मैचमेकिंग सेंटर का सहारा लिया और करीब 200 युआन (लगभग 2,300 रुपये)

देकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया. कुछ ही समय बाद मैचमेकर ने गु की मुलाकात शानक्सी प्रांत की 30 साल के महिला से कराई.

महिला की प्रोफाइल में दावा किया गया था कि उस पर कोई कर्ज नहीं है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह गंभीर बीमारी से भी पीड़ित नहीं है. इतना ही नहीं, वह जल्दी शादी करने और दूसरे शहर में बसने के लिए भी तैयार थी.

दोनों के बीच पहली बातचीत वीडियो कॉल पर हुई, जो महज 5 मिनट चली. गु ने महिला से उसके काम और परिवार के बारे में कुछ सवाल पूछे, लेकिन ज्यादातर जवाब मैचमेकर ने ही दिए. ⊙

फैंस के लिए सरप्राइज से कम नहीं 'रामायण' की एक्सक्लूसिव झलक

रणबीर कपूर और यश ने दिखाई 'रामायण' फिल्म की झलक

150 से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खास इवेंट, 15 मिनट के प्रेजेंटेशन ने बढ़ाई उत्सुकता

मुंबई, शुक्रवार

बॉलीवुड की सबसे चर्चित और बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है। अब फिल्म के मेकर्स ने इस एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। हाल ही में फिल्म के लीड स्टार्स रणबीर कपूर और यश ने 150 से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक खास इवेंट आयोजित किया, जहां उन्हें फिल्म की एक्सक्लूसिव झलक

इस इवेंट में मौजूद लोगों को करीब 15 मिनट का खास प्रेजेंटेशन दिखाया गया। इसमें फिल्म के कई ऐसे विजुअल्स शामिल थे, जिन्हें अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया था। इसके अलावा मेकिंग, बड़े-बड़े सेटूस और पर्दे के पीछे की मेहनत की भी झलक दिखाई गई।

कौन निभा रहा है कौन-सा किरदार?

- **रणबीर कपूर** – भगवान राम
- **साई पल्लवी** – माता सीता
- **रवि दुबे** – लक्ष्मण
- **यश** – रावण
- **सनी देओल** – भगवान हनुमान

रणबीर कपूर और यश को साथ देखकर खुश हुए फैंस

इवेंट की सबसे बड़ी हाइलाइट रणबीर कपूर और यश की मौजूदगी रही। दोनों स्टार्स ने कंटेंट क्रिएटर्स से मुलाकात की और तस्वीरें भी खिंचवाई। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई, खासकर इसलिए क्योंकि फिल्म में दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने नजर आने वाले हैं।

दो पार्ट में रिलीज होगी फिल्म

पहला पार्ट
दिवाली 2026 पर दुनियाभर के IMAX सिनेमाघरों में रिलीज होगा।

दूसरा पार्ट
दिवाली 2027 में दर्शकों के सामने आएगा।

भव्य निर्माण, दमदार टीम

फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं। इसका निर्माण नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज, ऑस्कर विजेता VFX कंपनी DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस मिलकर कर रहे हैं।

> "यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था की सबसे बड़ी सिनेमाई प्रस्तुति हैं।"
>
> – मेकर्स

लखनऊ में डेढ़ घंटे के भीतर दो जगह लगी आग, समय रहते टला बड़ा हादसा

लखनऊ में शुक्रवार सुबह डेढ़ घंटे के भीतर लोकबंधु अस्पताल के आशा ज्योति केंद्र और अमीनाबाद की सिंगार महल मार्केट में आग लग गई। दमकल ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। दोनों घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई, जबकि बिजली विभाग की लापरवाही के आरोप लगे।

लखनऊ के अलीगंज के भीषण अग्निकांड के बाद भी राजधानी में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। शुक्रवार सुबह करीब डेढ़ घंटे के भीतर शहर के दो अलग-अलग इलाकों में आग लग गई। पहला मामला कानपुर रोड स्थित लोकबंधु अस्पताल परिसर में संचालित आशा ज्योति (वन स्टॉप) सेंटर का रहा, जबकि दूसरा मामला अमीनाबाद के गड़बड़झाला स्थित सिंगार महल मार्केट की एक दुकान में सामने आया। दोनों घटनाओं में समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि, वन स्टॉप सेंटर की घटना के बाद बिजली विभाग और दमकल विभाग की लापरवाही सामने आई हैं। सेंटर प्रभारी का कहना है कि गुरुवार शाम से बिजली बार-बार ट्रिप होने की शिकायत के बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। आग लगने के बाद भी जेई समेत कई कर्मचारियों को फोन किए गए, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह 5:50 बजे फायर स्टेशन आलमबाग को सूचना मिली कि लोकबंधु अस्पताल परिसर में संचालित आशा ज्योति केंद्र में आग लग गई है। सूचना मिलते ही प्रभारी अग्निशमन अधिकारी धर्मपाल सिंह आलमबाग फायर स्टेशन से दो फायर टेंडर मौके के लिए रवाना किए गए। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि आग आशा ज्योति केंद्र के लाइट पैनल में लगी थी और लोकबंधु अस्पताल के अग्निशमन कर्मी पहले से ही आग बुझाने में जुटे हुए थे। फायर कर्मियों ने तत्काल हौज पाइप बिछाकर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। आग में लाइट पैनल और फॉल्स सीलिंग टूट हो गई, जबकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आशा ज्योति केंद्र की प्रभारी अर्चना सिंह ने बताया कि गुरुवार शाम से ही बिजली बार-बार ट्रिप हो रही थी। इसकी सूचना बिजली विभाग को दी गई थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। शुक्रवार सुबह आग लगने के बाद जेई समेत विभागीय अधिकारियों को कई बार फोन कर विद्युत आपूर्ति बंद कराने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद दमकल की गाड़ी करीब एक घंटे बाद मौके पर पहुंची। तब तक लोकबंधु अस्पताल के कर्मचारियों की मदद से आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था। शुक्रवार सुबह 5:38 बजे फायर स्टेशन हजरतगंज कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि अमीनाबाद के गड़बड़झाला स्थित सिंगार महल मार्केट में दुकान संख्या-81 में आग लग गई है। दुकान सिद्दीकी खान की बताई गई है। हजरतगंज और अमीनाबाद फायर यूनिट की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। जांच में पता चला कि आग दुकान के एयर कंडीशनर (एसी) में लगी थी। दुकान का शटर बंद था, जिसे काटकर दमकल कर्मियों ने मोटर फायर इंजन की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। इस घटना में भी कोई जनहानि नहीं हुई।

लखनऊ में भीषण गर्मी जारी, हीटवेव जैसी स्थिति से लोग परेशान

लखनऊ में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मानसून पहुंचने में देरी होने के चलते लोगों को तपन और उमस झेलनी पड़ रही है। आज, शुक्रवार दोपहर से शुरू हुई बादलों की आवाजाही से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। सुबह से आसमान साफ रहा और तेज धूप निकलने से उमसभरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मौसम विभाग ने दिन में हीटवेव जैसी स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक, आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक रहा। अधिकतम आर्द्रता 61 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 42 फीसदी रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राज्य में अभी कोई मजबूत वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है। इस वजह से तापमान में थोड़ी और बढ़ोतरी हो सकती है। 27 जून तक पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में लू का प्रकोप बना रहेगा। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है।

KGMU मरीज को निजी अस्पताल ले जाने वाले रेजिडेंट डॉक्टर पर होगी कार्रवाई

KGMU के मरीज को प्राइवेट हॉस्पीटल ले जाकर ऑपरेशन करने के आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर की जांच पूरी हो गई है। KGMU से पढ़ाई पूरी होने के बाद रेजिडेंट की बॉन्ड के तहत लोहिया संस्थान में तैनाती हुई है। हालांकि, KGMU प्रशासन की तरफ से रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ शासन स्तर से कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। वहीं, CMO ऑफिस की तरफ से निजी अस्पताल के खिलाफ जांच बैठाने का दावा भी किया जा रहा है। अंबेडकरनगर निवासी विनय दुबे ने 6 जून को पत्नी कमलेश देवी को KGMU में भर्ती कराया था। आरोप है कि डॉक्टर अमित ने बेहतर इलाज का झांसा देकर कृष्णानगर स्थित एसवीएम हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। इसके लिए करीब 45 हजार लिए। आरोप है कि डॉ.अमित ने कमलेश का ऑपरेशन किया। उन्हें खून चढ़ाया गया। विनय का आरोप है कि पत्नी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था, जबकि नए पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया। इससे स्थिति हालत नाजुक होने पर 16 जून को दोबारा KGMU में भर्ती कराया गया, जहां 20 जून की शाम कमलेश की मौत हो गई। KGMU की जांच में पता चला है कि डॉक्टर अमित अपनी पढ़ाई संस्थान से पूरी कर चुका है। बॉन्ड के तहत काउंसिलिंग के बाद उसे लोहिया संस्थान में तैनाती मिल गई है। KGMU प्रवक्ता डॉ. केके सिंह का कहना है कि शासन से डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। नर्सिंग होम के नोडल डॉ. एपी सिंह ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी। अस्पताल संचालक को नोटिस जारी कर इलाज से जुड़े दस्तावेज मांगे गए। इसके बाद से जांच ठंडे बस्ते में है। आरोप है कि अफसर मामला निपटाने में जुटे हैं। डॉ. एपी सिंह के मुताबिक, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।

छह साल बाद एलडीए से विदा हुए ज्ञानेंद्र वर्मा, कानपुर विकास प्राधिकरण भेजे गए

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया है। शासन ने उन्हें कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) में नई जिम्मेदारी सौंपी है। ज्ञानेंद्र वर्मा पिछले करीब छह सालों से एलडीए में तैनात थे और प्राधिकरण की कई अहम शाखाओं व संपत्तियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, उनका तबादला पहले ही कर दिया गया था, लेकिन एलडीए की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की लॉन्चिंग और प्रशासनिक कार्यों को देखते हुए उनकी कार्यमुक्ति रोक दी गई थी। अब योजनाओं की औपचारिक शुरुआत होने के बाद उन्हें कार्यमुक्त किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ज्ञानेंद्र वर्मा के कार्यकाल में एलडीए की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं, संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासनिक निर्णयों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्राधिकरण की व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों से जुड़े कई अहम मामलों की जिम्मेदारी भी उनके पास थी। उनके तबादले के बाद अब एलडीए में अपर सचिव स्तर की जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं, उनके स्थान पर किस अधिकारी की तैनाती होगी, इस संबंध में फिलहाल अलग से आदेश जारी नहीं हुआ है। शासन के इस फैसले को एलडीए के प्रशासनिक ढांचे में अहम बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

गोमतीनगर में पेट्रोल पंप पर मारपीट
महिला ग्राहक से अभद्रता का आरोप

लखनऊ के गोमतीनगर क्षेत्र स्थित हुसड़िया चौराहे के पास एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कम डालने के आरोप को लेकर विवाद हिंसक हो गया। आरोप है कि शिकायत करने पर पेट्रोल पंप के मैनेजर ने महिला ग्राहक से अभद्रता और गाली-गलौज की। विरोध बढ़ने पर कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर रहे लोगों पर हमला बोल दिया। गोमतीनगर विस्तार निवासी आकांक्षा दीक्षित की ओर से दी गई तहरीर के मुताबिक, वह स्कूटी में पेट्रोल भरवाने पहुंची थीं। उन्होंने कम पेट्रोल डाले जाने की शिकायत की तो मैनेजर ने अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद कई कर्मचारियों ने कथित तौर पर पत्थरों, लात-घूंसों से हमला कर दिया। इस घटना में रमन सोनी, दिव्यांशु पांडेय, अधिवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह, अभिजीत मानस समेत कई लोग घायल हो गए। रमन सोनी का मुंह फटने और दांत टूटने का भी आरोप है। महिला के अनुसार, भीड़ बढ़ने पर कुछ कर्मचारी मौके से फरार हो गए, जबकि एक कर्मचारी को पकड़ लिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे थाने ले गई। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने गोमतीनगर थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अलीगंज अग्निकांड के बाद सख्ती, एलडीए ने कोचिंग और लाइब्रेरी पर कार्रवाई तेज की

लखनऊ में 15 मौतों के बाद एलडीए एक्शन में है। दो दिन की कार्रवाई में एलडीए ने LDA ने 126 प्रतिष्ठान सील किए, जबकि 161 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया। मानक पूरे नहीं होने पर टीम ने गोमतीनगर की भूमि IAS कोचिंग, विद्या मंदिर कोचिंग और दृष्टिकोण लाइब्रेरी सील कर दी है। बच्चे सड़कों पर परेशान दिखे। हर किसी का एक ही सवाल था- अब क्या होगा? LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर शुरू हुआ यह अभियान लगातार 3 सप्ताह तक चलाया जाएगा। इसमें कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, होटल, नर्सिंग होम, डांस स्टूडियो, प्ले ग्रुप स्कूल और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की जांच की जाएगी। LDA अफसरों का कहना है कि जिन भवनों में अग्नि सुरक्षा, पार्किंग और मानचित्र संबंधी मानकों का उल्लंघन मिलेगा, उनके खिलाफ सीलिंग और नोटिस की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, 24 जून (बुधवार) को सुरक्षा मानकों को अनदेखी करके चल रहे 71 प्रतिष्ठानों को सील किया गया था। इनमें एलन, ग्रेविटी, आकाश, गवर्नमेंट एग्जाम वाला और पैरामाउंट जैसे बड़े कोचिंग संस्थान शामिल रहे। एलडीए ने 83 भवन मालिकों को नोटिस भी जारी किया था। अलीगंज स्थित एक इमारत में 22 जून को आग लग गई थी। यहां बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लीनिक थी। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी (कोचिंग) और हेड हॉपर स्टूडियो था। इसमें 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता था। हॉपर स्टूडियो में काम करने वाले 15 लोगों की मौत हो गई थी।

पोस्टमार्टम हाउस में अव्यवस्थाओं पर भड़के विधायक,

24 घंटे में सुधार के निर्देश

उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता ने शुक्रवार दोपहर पोस्टमार्टम हाउस का औचक निरीक्षण किया। उन्हें लंबे समय से यहां अव्यवस्थाओं की शिकायतें मिल रही थीं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए बैठने की जगह पर पंखों की कमी और पीने के पानी की समस्या पाई। विधायक ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। विधायक पंकज गुप्ता ने बताया कि उन्हें पिछले कई दिनों से पोस्टमार्टम हाउस में सुविधाओं के अभाव की शिकायतें मिल रही थीं। विशेष रूप से, परिजनों के बैठने वाले स्थान पर पंखे न होने और ठंडे पानी की व्यवस्था खराब होने की शिकायतें प्रमुख थीं। इन्हीं समस्याओं का जायजा लेने के लिए उन्होंने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने पाया कि परिजनों के बैठने के स्थान पर पंखों की उचित व्यवस्था नहीं थी। इसके अतिरिक्त, ठंडे पानी के लिए लगाई गई मशीन भी बंद मिली। गर्मी के मौसम में दूर-दराज से आने वाले शोकाकुल परिजनों को होने वाली परेशानी को देखते हुए विधायक ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने मौके से ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को समस्याओं के तत्काल समाधान के निर्देश दिए। विधायक के निर्देश के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने विधायक के साथ मिलकर पोस्टमार्टम हाउस का निरीक्षण किया और संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को जल्द से जल्द पंखों और पेयजल व्यवस्था को ठीक कराने के निर्देश दिए। सीएमओ ने आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम हाउस की सभी व्यवस्थाओं को शीघ्र ही दुरुस्त कर दिया जाएगा। विधायक पंकज गुप्ता ने जोर देकर कहा कि मृतक परिजन पहले ही दुख की स्थिति में होते हैं, ऐसे में उन्हें मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना उचित नहीं है। उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस इंचार्ज को 24 घंटे के भीतर सभी व्यवस्थाएं सुधारने का अल्टीमेटम दिया। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि तय समय में सुधार नहीं किया गया तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उन्नाव में युवती का रिवॉल्वर संग रील वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच

उन्नाव में एक युवती का रिवॉल्वर के साथ बनाया गया रील बनाया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और दबदबा दिखाने के लिए हथियारों के साथ वीडियो बनाने के लगातार सामने आ रहे सिलसिले का हिस्सा है। वीडियो में युवती कार के अंदर बैठी दिखाई दे रही है। उसके हाथ में रिवॉल्वर है, जिसे वह बेखौफ अंदाज में लहरा रही है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो इंस्टाग्राम पर 'shalinismiloveyou' नाम के हैंडल से अपलोड किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे वीडियो युवाओं में गलत संदेश पहुंचा सकते हैं और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वीडियो में दिख रही युवती मौरावां थाना क्षेत्र के गालिबपुर गांव की बताई जा रही है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक युवती की पहचान या वीडियो में दिख रहे हथियार की पुष्टि नहीं की है। मौरावां थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वीडियो में दिख रहा रिवॉल्वर लाइसेंसी है या अवैध। साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि वीडियो कब और कहां बनाया गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करना कानून के दायरे में आता है और ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

मजदूर की बेटी को 20.98 करोड़ की आय छिपाने का आयकर विभाग का समन

उन्नाव के गिरिजाबाग मोहल्ले में रहने वाली बीए की छात्रा रश्मि सविता को आयकर विभाग ने 20.98 करोड़ रुपये की आय छिपाने और बड़े कारोबार से जुड़े लेनदेन के संबंध में समन भेजा है। मजदूर परिवार से ताल्लुक रखने वाली रश्मि और उनके परिजनों ने इस पर हैरानी जताई है। रश्मि सविता को यह समन 30 अप्रैल को आयकर विभाग चंडीगढ़ की ओर से आयकर अधिनियम की धारा 131(1A) के तहत जारी किया गया था। इस धारा के तहत आमतौर पर आय छिपाने या वित्तीय अनियमितताओं की आशंका होने पर जांच की जाती है। समन में रश्मि को पांच मई तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। नोटिस मिलने के बाद रश्मि ने मामले की जानकारी जुटाने के लिए विभिन्न विभागों से संपर्क किया। जांच में उन्हें पता चला कि उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड का कथित तौर पर दुरुपयोग कर दिल्ली में एक फर्म खोली गई थी। आरोप है कि उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल संतनगर, बुराड़ी क्षेत्र में 'आरएस इंटरप्राइजेज' नामक फर्म के संचालन के लिए किया गया। रश्मि के अनुसार, यह फर्म 15 जनवरी 2025 को शुरू हुई थी और 9 मई 2025 को बंद कर दी गई। लगभग पांच महीने तक उनके दस्तावेजों के आधार पर कारोबार किए जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, रश्मि का कहना है कि उन्हें इस फर्म या किसी भी प्रकार के करोड़ों रुपये के कारोबार की कोई जानकारी नहीं थी। रश्मि के पिता अजय शंकर मजदूरी करते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य है। उनका जीवन-यापन मेहनत-मजदूरी से चलता है। ऐसे में 20.98 करोड़ रुपये की आय और व्यापार से जुड़ा समन मिलने के बाद पूरा परिवार चिंतित है। रश्मि ने कानूनी प्रक्रिया के तहत आयकर विभाग को अपना जवाब भेज दिया है। साथ ही उसने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए पैन कार्ड और आधार कार्ड के दुरुपयोग की आशंका जताई है। उसने पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र देकर मामले में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

उन्नाव में पुलिस अधिकारियों के लिए बनेंगे चार नए गेस्ट हाउस

उन्नाव में पुलिस विभाग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के ठहरने और विभागीय कार्यों के लिए चांदमारी बट में चार नए गेस्ट हाउसों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इन गेस्ट हाउसों के निर्माण पर 2 करोड़ 86 लाख 50 हजार रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी। जनपद में बाहर से आने वाले राजपत्रित अधिकारियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण उन्हें अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या को देखते हुए शासन स्तर से गेस्ट हाउस निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसे अब स्वीकृति मिल गई है। विशेष सचिव दिनेश कुमार ने अपर पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर निर्माण कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। शासनादेश के अनुसार, ये चारों गेस्ट हाउस जनपद के दारोगा बाग स्थित चांदमारी बट में बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सी एंड डीएस जल निगम को सौंपी गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, निर्माण शुरू करने से पहले सभी आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। इसमें जरूरी अनापत्तियां, पर्यावरणीय मंजूरी और तकनीकी स्वीकृतियां शामिल हैं। शासन की ओर से यह भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रस्तावित निर्माण कार्य किसी अन्य योजना के तहत पहले से स्वीकृत न हो और किसी प्रकार का दोहराव न किया जाए। स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल इसी परियोजना के लिए किया जाएगा, जिसकी समय सीमा 31 मार्च 2027 तक निर्धारित की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इन गेस्ट हाउसों के बनने के बाद जिले में आने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अन्य राजपत्रित अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था बेहतर हो सकेगी। पुलिस विभाग का मानना है कि इस निर्माण से प्रशासनिक कार्यों में भी सुविधा मिलेगी और विभागीय गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।

उन्नाव में मेगा हेल्थ कैम्प का आयोजन

उन्नाव के पार्क व्यू पैलेस गेस्ट हाउस में अभ्युदय सेवा संस्थान द्वारा एक मेगा हेल्थ कैम्प का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में चिकित्सकों, समाजसेवियों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। उन्नाव सदर विधानसभा के विधायक पंकज गुप्ता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक पंकज गुप्ता के साथ इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी के सभापति अमित मिश्रा भी मौजूद थे। अमित मिश्रा ने सम्मानित चिकित्सकों और आयोजन समिति से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों को पटका एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इसके जवाब में, आयोजन समिति के सदस्यों ने अमित मिश्रा को भी पटका पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम का आयोजन प्रभात सिन्हा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस हेल्थ कैम्प में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बड़ी संख्या में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। उन्हें आवश्यक परामर्श प्रदान करने के साथ-साथ दवाइयों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के समापन पर, आयोजकों ने सभी अतिथियों, चिकित्सकों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने भविष्य में भी जनसेवा के ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने का संकल्प दोहराया।

मोहर्रम पर उन्नाव में निकले अलम और ताजिया जुलूस

उन्नाव में शुक्रवार को मोहर्रम के अवसर पर इमाम हुसैन की शहादत की याद में अलम और ताजिया जुलूस निकाले गए। ये जुलूस नगर के विभिन्न मुस्लिम बहुल इलाकों से शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुए और शाम तक गंगाघाट क्षेत्र स्थित कर्बला पहुंचे, जहां ताजियों को दफन किया गया। इस दौरान नगर में गम का माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोगों ने इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया। दोपहर करीब बारह बजे शुक्लागंज के अहमद नगर, रहमत नगर, मनोहर नगर, अली नगर, मदनीनगर और चम्पापुरवा सहित कई मोहल्लों से ताजियों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद सभी ताजियों को राजधानी मार्ग स्थित जामा मस्जिद में एकत्र किया गया। यहां से एक साथ जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ निर्धारित गंतव्य की ओर बढ़ा। जुलूस के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। थाना प्रभारी अजय सिंह स्वयं बल के साथ जुलूस में मौजूद रहे। कुछ स्थानों पर भीड़ के कारण यातायात बाधित हुआ, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से स्थिति को संभाला, जिससे आम नागरिकों को कोई परेशानी नहीं हुई। जुलूस के दौरान युवाओं ने कई खतरनाक करतब दिखाए, जिन्होंने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। इनमें मुंह से आग के गोले फेंकना, सिर पर ट्यूबलाइट फोड़ना और तलवारों-भालों से जांबाजी का प्रदर्शन करना शामिल था। इन दृश्यों को देखकर दर्शक रोमांचित हुए और उन्होंने करतबबाजों का उत्साहवर्धन किया।

पंचायत चुनाव टालने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव टालने और ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार से जवाब, OBC रिपोर्ट और चुनाव की टाइमलाइन मांगी है। निर्वाचन आयोग तैयार है, अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने और ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मामले पर शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जताई। यह मामला सहारनपुर निवासी अरविंद राठौर द्वारा दाखिल याचिका से जुड़ा है, जिस पर जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में कैसे नियुक्त किया गया, जबकि यह पहले से ही डिवीजन बेंच के आदेश का उल्लंघन है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यह स्थिति अवमानना की श्रेणी में आती है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जिन आदेशों के आधार पर ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की कोशिश की गई, उन्हें पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। अदालत ने यह दोहराया कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव कराना अनिवार्य है और इसे टाला नहीं जा सकता। कोर्ट ने सरकार से हलफनामे के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट और पंचायत चुनाव की स्पष्ट टाइमलाइन पेश करने को कहा है। हालांकि, फिलहाल अदालत ने किसी प्रकार की अंतरिम रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के लिए आयोग पूरी तरह तैयार है। आयोग ने जानकारी दी कि 10 जून 2026 को मतदाता सूची भी प्रकाशित कर दी गई है। आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं और सहयोग नहीं मिलने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। याचिका में मांग की गई है कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के आदेश को रद्द किया जाए और जल्द से जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएं। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई की तारीख 13 जुलाई 2026 तय की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ सकता है।इस बीच, राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट के रुख पर टिप्पणी करते हुए सरकार पर तंज कसा। उन्होंने एक कविता के माध्यम से कहा कि भाजपा अपने निर्णयों के कारण असफल साबित हो रही है।गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका है। इसके बाद 25 मई को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया था। साथ ही पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर आंकलन के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसे छह महीने का समय दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया के बीच चुनाव टलने को लेकर सवाल उठते रहे हैं और मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है।

कौशांबी में LPG टैंकर टोल प्लाजा से टकराया, भीषण धमाके के बाद लगी आग

यूपी के कौशांबी में शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे एक LPG टैंकर बेकाबू होकर टोल प्लाजा से टकरा गया। टक्कर के बाद तेज धमाका हुआ और टैंकर में आग लग गई। हादसे में टैंकर चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। उसका शव पूरी तरह जल गया और कंकाल का कुछ हिस्सा ही बरामद हो सका। वहीं, पांच टोल कर्मचारी भी झुलस गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक टैंकर पूरी तरह जल चुका था। टोल प्लाजा के यार्ड में खड़ी 16 बाइकें और दो कारें भी आग की चपेट में आकर जल गईं। आग बुझने के बाद जब टीम टैंकर के अंदर पहुंची तो चालक की हड्डियां मिलीं। इससे पहले सूचना मिली थी कि चालक टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल हो गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। आग की ऊंची लपटों को देखकर टोल प्लाजा के दोनों ओर बसों और कारों की लंबी कतारें लग गईं। करीब 2 किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार और आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। यह हादसा जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर कोखराज थाना क्षेत्र के सिहोरी टोल प्लाजा पर हुआ।

कानपुर: गलत पहचान में 5 साल जेल में रहा युवक

'25 मई 2021 की रात बिधनू थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह के साथ कुछ पुलिसवालें घर आ गए। उन्होंने पूछा कि विक्की कौन है...? मैंने उनसे कहा कि मेरा नाम अमीन लायल है, लेकिन वो नहीं माने और मुझे उठाकर थाने ले गए। वहां उन्होंने मुझे जमकर पीटा और कहा कि कबूल करों की तुम ही विक्की हो। पुलिसवालों ने मुझे इतना पीटा की मेरे कान का पर्दा तक फट गया। मुझे एक कान से आज तक सुनाई नहीं देता है। मेरे पिता थाने में मेरी बेगुनाही के सबूत देते रहे, लेकिन पुलिसवालों ने नहीं सुनी और 2 दिन थाने में बिठाने के बाद मुझे विक्की बताकर जेल भेज दिया, मुझे आज तक नहीं पता चला कि किस वजह से पुलिसवालों ने मुझे जेल में ठूंस दिया था। मैं विक्की नहीं हूं... यह साबित करने में मेरे परिवार को पांच साल लग गए। पुलिसवालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।' ये आपबीती बिधनू के अमीन लायल की है। अमीन लायल, बिना किसी जुर्म के ही एक 13 साल की किशोरी के रेप के मामले में 5 साल की जेल काट कर रिहा हुए हैं। कानपुर की स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने युवक अमीन लायल को बरी कर दिया है। पीड़िता की मां के बयान के आधार पर उसे बाइज्जत बरी किया गया है। कोर्ट ने बिधनू थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह और विवेचना में शामिल अन्य पुलिसवालों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी पुलिस कमिश्नर और डीएम को निर्देश दिया है।

अयोध्या में आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा: सीएम योगी

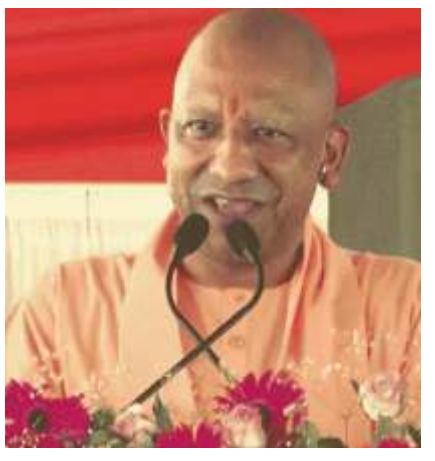

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शुक्रवार को देवरिया में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद मामले में तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनआस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और "दूध का दूध और पानी का पानी" कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग राम मंदिर या अयोध्या पर आरोप लगा रहे हैं, उनके पास यदि कोई प्रमाण है तो उसे एसआईटी को सौपें, अन्यथा इस तरह के आरोप लगाना बंद करें। उन्होंने कहा कि राम भक्तों की आस्था के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को सिर्फ लूटा ही नहीं बल्कि "नोंचा" है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने कभी भगवान राम के नाम पर गोली चलवाई, वही आज आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सीएम ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे लोग उन्हें आस्था का पाठ नहीं पढ़ा सकते। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर भी तंज कसा। योगी ने कहा कि दिल्ली में 15 वर्षों में विकास नहीं हुआ और राजधानी को बर्बाद किया गया। उन्होंने कहा कि अयोध्या आकर लोग यहां की प्रगति देखें और यदि दिल्ली में भी ऐसा काम किया होता तो शहर भी इसी तरह चमकता।